भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2317

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

क्षेत्र कौशल परिषदों की स्थिति

2317. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर: श्रीमती भारती पारधी: श्री नरेश गणपत म्हस्के: श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील: श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, विशेषकर मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और रायगढ़, पुणे और मध्य प्रदेश की बालाघाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) कार्यरत हैं;

(ख) विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विनिर्माण, संभारतंत्र, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए कौशल कमियों की पहचान करने और योग्यता मानक निर्धारित करने के लिए इन क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का क्या अधिदेश है;

(ग) उक्त राज्यों में एसएससी द्वारा पहचान की गई कौशल आवश्यकताओं का ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) उक्त राज्य में विशेषकर मुंबई महानगर क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; और

(ड.) उक्त राज्यों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए वित्तपोषण, पाठ्यचर्या विकास और प्रमाणन सहित एनएसडीसी सहायता की विशिष्टताएं क्या हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) राज्य-विशिष्ट निकायों के बजाय उद्योग-केंद्रित स्वायत्त संगठनों के रूप में स्थापित की जाती हैं, जिनमें से कुल 36 एसएससी का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। एसएससी को उद्योग-अनुरूप कौशल मानक परिभाषित करने, कार्यबल आवश्यकताओं का आकलन करने और क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। ये परिषदें समय-समय पर कौशल अंतर और कौशल मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न उद्योगों में कार्यबल की आवश्यकताएं, उभरते हुए जॉब रोल्स और प्रशिक्षण की जरूरतें उजागर होती हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में एसएससी द्वारा किए गए कौशल अंतर अध्ययनों का मुख्य ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) से (च): एनएसडीसी पूरे भारत में कौशल विकास पहलों को सशक्त बनाने के लिए उद्यमों, स्टार्ट-अप, कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों सहित प्रशिक्षण प्रदाताओं को संरचित सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में प्रशिक्षण केंद्रों का पंजीकरण और मान्यता, गुणवत्ता आश्वासन, प्रशिक्षण परिणामों की निगरानी, उद्योग से संबंध स्थापित करना और मूल्यांकन को सक्षम बनाना शामिल है। प्रशिक्षण प्रदाता राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसका लक्ष्य बेरोजगार युवा, स्कूल छोड़ने वाले छात्र, वंचित समुदाय और नियोजनीयता में वृद्दि की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, साथ ही यह उद्योग की कार्यबल आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। प्रशिक्षण लक्ष्य क्षेत्र की मांग, प्रदर्शन और भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रशिक्षण के परिणाम बेहतर रोजगार, स्वरोजगार या उद्यमशीलता के अवसरों की ओर ले जाएं। ये पद्धतियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में लागू होती हैं, और सहायता का दायरा योजना के प्रावधानों, स्वीकृतियों और व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

अनुबंध-।

'क्षेत्र कौशल परिषद की स्थिति' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 15.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2317 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

36 क्षेत्रीय कौशल परिषद की सूची

क्र.सं.	एसएससी का नाम
1	एयरोस्पेस और विमानन क्षेत्र कौशल परिषद
2	भारतीय कृषि कौशल परिषद
3	परिधान, मेडअप्स और होम फर्निशिंग क्षेत्र कौशल परिषद
4	ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद
5	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा क्षेत्र कौशल परिषद भारत
6	सौंदर्य और स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद
7	पूंजीगत वस्तुएँ और कार्यनीतिगत कौशल परिषद
8	भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद
9	गृह प्रबंधन और देखभालकर्ता क्षेत्र कौशल परिषद
10	इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद ऑफ इंडिया
11	खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल
12	फर्नीचर और फिटिंग कौशल परिषद
13	भारतीय रत्न एवं आभूषण कौशल परिषद
14	हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल परिषद
15	स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कौशल परिषद
16	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद
17	भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद
18	बुनियादी ढांचा उपकरण कौशल परिषद
19	इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन सर्विलांस और कम्युनिकेशन क्षेत्र कौशल परिषद
20	आईटी- आईटीईएस क्षेत्र कौशल परिषद
21	चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद
22	जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद
23	लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कौशल परिषद
24	प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद
25	मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद
26	विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद
27	भारतीय खुदरा संबद्ध कौशल परिषद
28	रबर, रसायन और पॉलिमर कौशल विकास परिषद
29	ग्रीन जॉब्स के लिए कौशल परिषद
30	खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद
31	दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद
32	खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और अवकाश क्षेत्र कौशल परिषद
33	भारतीय दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद
34	कपड़ा क्षेत्र कौशल परिषद
35	पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद
36	जल प्रबंधन और नलसाजी कौशल परिषद

अनुबंध-II

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए कौशल अंतर अध्ययनों का मुख्य विवरण

क्र.सं.	एसएससी का नाम	मुख्य विवरण
1	**लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कौशल परिषद**	लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कौशल परिषद की 2024 कौशल अंतर और जनशक्ति मांग रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2030 तक कार्यबल की भारी आवश्यकता रहेगी। महाराष्ट्र में 4,20,526 कर्मियों की अतिरिक्त मांग देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण भूमि परिवहन, कूरियर और एक्सप्रेस सेवाएं, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, रेल लॉजिस्टिक्स, एक्सआईएम, एयर कार्गो, पोर्ट टर्मिनल और अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। पुणे, मुंबई महानगर क्षेत्र और रायगढ़ जैसे प्रमुख जिलों में ड्राइवरों (एलजीवी/एचजीवी), डिलीवरी एक्जीक्यूटिव, वेयरहाउस और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, एयर कार्गो कर्मचारी, ईएक्सआईएम(एक्सिम) डॉक्यूमेंटेशन स्टाफ और पोर्ट/आईसीडी/सीएफएस कामगारों की अधिक मांग रहेगी। मध्य प्रदेश में अनुमानित तौर पर 2,45,646 अतिरिक्त कामगारों की आवश्यकता होगी, जिनमें मुख्य रूप से सड़क परिवहन, कूरियर सेवाएं, भंडारण, कोल्ड चेन, रेल लॉजिस्टिक्स, एक्जिमायंट इंपोर्ट (ईएक्सआईएम), हवाई कार्गो और आईसीडी-सीएफएस संचालन शामिल हैं। बालाघाट जैसे जिलों में ही उल्लेखनीय मांग देखी जा रही है, जहां सड़क परिवहन में लगभग 2,300 पद, एक्सप्रेस सेवाओं में 560 पद और भंडारण एवं कोल्ड चेन में 210 पद उपलब्ध हैं।
2	**खाद्य उद्योग क्षमता तथा कौशल पहल**	खाद्य उद्योग कौशल परिषद (एफआईएससीआई) ने 2022 में एक कौशल अंतर रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें 2030 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए राज्यवार रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता महाराष्ट्र में 171,319 और मध्य प्रदेश में 36,119 होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2030 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर उप-क्षेत्रवार मांग निम्नलिखित है: डेयरी: 2,73,571 2,59,201 मछली और समुद्री खद्य: 2,59,201 1,86,750 ब्रेड और बेकरी: 1,86,750 पिसाई(मिलिंग): 1,23,335
3	**सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद**	सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद की 2022 कौशल अंतर रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक इस क्षेत्र में रोजगार की प्रबल संभावना है, जिसके तहत महाराष्ट्र में 12,06,102 और मध्य प्रदेश में 8,54,508 अतिरिक्त पेशेवरों की आवश्यकता होगी। हालांकि राज्य-विशिष्ट उपक्षेत्र और जॉब रोल्स के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वित्त वर्ष 2022-2030 के लिए राष्ट्रीय स्तर के पूर्वानुमान में ब्यूटी एंड सैलून सेवाओं, वैकल्पिक थेरेपी, एस्थेटिक स्किन सेवाओं, कायाकल्प और स्पा,

		उत्पाद निर्माण और बिक्री, योग, फिटनेस और वेट (वजन) प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारी मांग को दर्शाया गया है। जिन प्रमुख व्यवसायों में अत्यधिक मांग देखने की उम्मीद है उनमें ब्यूटी थेरेपिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, नेल टेक्नीशियन, वेलनेस और स्पा थेरेपिस्ट, योग प्रशिक्षक, पर्सनल ट्रेनर, डर्मेटोलॉजी और लेजर टेक्नीशियन, स्लिमिंग और बॉडी थेरेपिस्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट आदि शामिल हैं - जो सौंदर्य, स्वास्थ्य, फिटनेस और समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रों में इस क्षेत्र के तेजी से विस्तार को दर्शाता है।
4	**पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद**	पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद की 2024 कौशल अंतर रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2028 तक रोजगार सृजन की प्रबल संभावना है। महाराष्ट्र, जिसकी विविध पर्यटन अर्थव्यवस्था में व्यापारिक केंद्र, विरासत शहर, धार्मिक स्थल, तटीय और प्रकृति-आधारित पर्यटन स्थल शामिल हैं, को अगले पांच वर्षों में 3.4 लाख कुशल कामगारों की आवश्यकता होने का अनुमान है। अकेले मुंबई में ही 18,000 से अधिक कामगारों की आवश्यकता होगी, जबकि पुणे, नासिक, शिरडी और लोनावला में होटलों, कैफे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, होमस्टे और टूर ऑपरेटर्स में सामूहिक रूप से काफी मांग होगी। प्राथमिकता वाले पदों में गेस्ट सर्विस एसोसिएट्स, फ्रंट ऑफिस एक्जीक्यूटिव, फूड एंड बेवरेज स्टीवर्ड, किचन स्टाफ, टूर गाइड, होमस्टे मैनेजर और प्रकृतिवादी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अगले पांच वर्षों में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 1.2 लाख से अधिक कुशल कामगारों की आवश्यकता होने का अनुमान है। राज्य के वाणिज्यिक और पाक कला केंद्र के रूप में इंदौर में होटलों, रेस्तरां, त्वरित सेवा रेस्तरां और कार्यक्रम स्थलों में 29,000 से अधिक पेशेवरों की मांग सबसे अधिक होगी। **उज्जैन-ओंकारेश्वर** तीर्थयात्रा गलियारे से मार्गदर्शक सेवाओं, हाउसकीपिंग और खाद्य एवं पेय संचालन में 24,000 से अधिक कुशल कामगारों की मांग उत्पन्न होने की उम्मीद है। भोपाल-**रायसेन-सीहोर** क्लस्टर, जो एमआईसीई और शहरी पर्यटन पर केंद्रित है, को 8,700 से अधिक कामगारों की आवश्यकता होगी, जबकि कान्हा-पेंच वन्यजीव क्षेत्र के पास स्थित **बालाघाट**, पर्यावरण पर्यटन और सामुदायिक यात्रा पर जोर देगा, जिसके लिए प्रकृतिवादियों, सामुदायिक टूर गाइडों, होमस्टे संचालकों और बुनियादी आतिथ्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। राज्य भर में प्राथमिकता वाले पदों में अतिथि सेवा सहयोगी, रसोई सहायक, फ्रंट ऑफिस सहयोगी, टूर गाइड, पैदल यात्रा सुविधाकर्ता, होमस्टे प्रबंधक और वन्यजीव पर्यटन प्रकृतिवादी शामिल हैं।
5	**हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी)**	हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) द्वारा दिसंबर 2025 में प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार, निम्नलिखित तालिका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक मांग के कुल योग को दर्शाती है।

राज्य	अगले 2 से 3 वर्ष में मांग	अगले 9 से 10 वर्ष में मांग	प्रमुख शिल्प

			मध्य प्रदेश	लगभग 1,20,000	लगभग 10,00,000	ज़री और ज़रदोज़ी कढ़ाई, बाघ प्रिंट (हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग), ढोकरा (लॉस्ट-वैक्स मेटल कास्टिंग), पत्थर की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, चमड़े के खिलौने (भरवां), बांस और बेंत का काम	
			महाराष्ट्र	लगभग 1,00,000	लगभग 5,00,000	कोल्हापुरी चप्पलें, बिदरीवेयर, तांबे और पीतल के बर्तन, वारली पेंटिंग, लकड़ी के खिलौने (सावंतवाड़ी), लाख की चूड़ियां, पिथौरा पेंटिंग, गोंड हस्तशिल्प (आदिवासी कला)	

*****